भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :902

दिनांक 2 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण,1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 के कारण नौकरियां खोना

902. श्री भर्तृहरी महताब:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोविड-19 जनित व्यवधान से देश में विमानन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी चली गई है;

(ख) यदि हां, तो एयरलाइनों, ग्राउंड हैडलिंग कंपनियों और कार्गो कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिन्होंने चालू वर्ष में अपना रोजगार खो दिया है;

(ग) क्या महामारी के दौरान कई एयरलाइनों ने स्टॉफ के वेतन में कटौती की है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार यात्रियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखते हुए यात्रा को प्रोत्साहन देने का है और यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़.) सरकार द्वारा विमानन उद्योग को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित अन्य आवश्यक कदम क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख) उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, विवरण निम्नानुसार हैं:

(1) अंतर्देशीय वाहकों के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च 2020 को लगभग 74,800 से घटकर 31 मार्च 2021 को लगभग 66,900 हो गई है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या में 7,900 से अधिक की गिरावट आई है।

(2) ग्राउंड हैंडलिंग में कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च 2020 को लगभग 38,330 से घटकर 31 मार्च 2021 को लगभग 25,040 हो गई है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या में लगभग 13,300 की गिरावट आई है।

3) कार्गो में कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च 2020 को लगभग 9,550 थी जो अब 31 मार्च 2021 को बढ़कर लगभग 9,930 हो गई है, जो लगभग 380 कर्मचारियों की वृद्धि है।

(ग) कुछ एयरलाइनों ने कोविड महामारी के मद्देनजर भत्तों के भुगतान को युक्तिसंगत बनाया था। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

(1) एयर इंडिया लिमिटेड:

प्रति माह 25,000/- रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई वेतन कटौती लागू नहीं की गई।

एक महीने में कम से कम 20 घंटे की उड़ान के अधीन, उड़ान भत्तों में कमी।

(2) एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड:

विशेष वेतन, घरेलू लेओवर भत्ता (domestic layover allowance), त्वरित वापसी भत्ता(quick return allowance), चेक भत्ता (check allowance), प्रशिक्षक भत्ता और परीक्षक भत्ता पर पायलटों के भत्ते में 40 प्रतिशत की कमी।

फ्लाइंग अलाउंस में 35 प्रतिशत की कटौती।

केबिन कर्मीदल के घरेलू लेओवर भत्ते में 20 प्रतिशत की कमी।

ग्रेड उप प्रबंधक और उससे ऊपर के कर्मचारियों के सकल वेतन से 7.5 प्रतिशत की कटौती।

(3) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड:

एक महीने में न्यूनतम 20 घंटे की उड़ान की शर्त पर, कमांडरों और सह-पायलटों के उड़ान भत्तों में कमी।

प्रवासी पायलटों के कुल वेतन में 40 प्रतिशत की कटौती।

अन्य ग्राउंड स्टाफ के सकल वेतन पर 5 प्रतिशत की कटौती।

(4) इंडिगो:

कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान, प्रबंधकीय स्तर और उससे ऊपर के कर्मचारियों के वेतन में 2.5 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक की कटौती लागू की गई थी, जिनमें से अधिकांश को अब तक

बहाल कर दिया गया है। प्रबंधकीय स्तर से नीचे के कर्मचारियों के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

(5) एयर एशिया:

50,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती लागू की गई। वेतन कटौती अब अक्टूबर 2021 से हटा दी गई है और नियमित वेतन बहाल कर दिया गया है।

(घ) और (ड.) सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विमानन उद्योग को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(1) कोविड प्रोटोकॉल को अपनाना, सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग, संपर्क-रहित यात्री हैंडलिंग प्रक्रियाएं जैसे कि 100 प्रतिशत ऑनलाइन चेक-इन, स्व-घोषणा पत्र जमा करना और सेल्फ बैगेज ड्रॉप आदि।

(2) नागर विमानन क्षेत्र को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 के तहत लाभ दिया गया।

(3) 31 देशों के साथ विशिष्ट एयर-लिंक्स या 'एयर बबल्स' स्थापित किए गए हैं।

(4) भाविप्रा ने अगले 4-5 वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान रखते हुए नए हवाईअड्डों का विकास और मौजूदा हवाईअड्डों का विस्तार / उन्नयन आरंभ किया है, जिसमें मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार और आशोधन, नए टर्मिनल, मौजूदा रनवे, एप्रन, एयरपोर्ट नेविगेशन सर्विसेज (एएनएस), कंट्रोल टावर, तकनीकी ब्लॉक आदि का विस्तार या सुदृढीकरण शामिल हैं।

(5) दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में तीन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) हवाईअड्डों ने 2025 तक 30,000 करोड़ रुपये की बड़ी विस्तार योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, पीपीपी मोड के तहत देश भर में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास में निवेश के लिए 36,000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।

(6) भारत सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रदान किया है। अब तक आठ ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों नामत: महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और शिरडी, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल, कर्नाटक में कलबुर्गी और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पर प्रचालन आरंभ किया जा चुका है।

(7) क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) के तहत, जिसे उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के रूप में भी जाना जाता है, 24 नवंबर 2021 को, 2 वॉटर ऐरोड्रोम और 6 हेलीपोर्ट सहित 62 अपरिचालित और अल्प परिचालित हवाईअड्डों को जोड़ते हुए 393 मार्गों पर प्रचालन आरंभ किया गया है।

(8) घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

(9) विमान को पट्टे पर देने और वित्तपोषण हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।

(10) एयरलाइंस की अंतर्देशीय क्षमता को 18 अक्टूबर 2021 से पूर्ण रूप से बहाल कर दिया गया है, जैसा कि पूर्व-कोविड समय में था।

(11) भारतीय हवाईअड्डों पर हवाई दिक्चालन के बुनियादी ढांचे में सुधार और उनमें अत्याधुनिक नवीनतम तकनीकों को शामिल करना।

(12) भारतीय वाहकों द्वारा तैनात मालवाहक विमान 2018 में 7 से बढ़कर 2021 में 28 हो गए हैं। सरकार की सक्रिय क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय मालवाहक आंदोलनों में भारतीय वाहकों की हिस्सेदारी पिछले दो वर्ष में 2 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गई है।

(13) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने पांच हवाईअड्डों, बेलगावी (कर्नाटक), जलगांव (महाराष्ट्र), कलबुर्गी (कर्नाटक), खजुराहो (मध्य प्रदेश) और लीलाबारी (असम) पर स्थापित होने वाले नौ एफटीओ के लिए 31 मई 2021 और 29 अक्टूबर 2021 को एवार्ड पत्र जारी किए हैं। कलबुर्गी में दो एफटीओ का सॉफ्ट लॉन्च 15 अगस्त 2021 को किया गया था।